राष्ट्रीय

छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 24 अंक : 2 नवम्बर 2001

- *OBITUARY OF GOWRI SHANKARJEE*
- *एस एफ आई के किले पर लहराया केसरिया*
- *TIME TO CONSTITUTE NATIONAL EDUCATION COMISSION*
- *विद्यार्थी संगठन एवं छात्रसंघ*
- *STUCTURE OF ECUCATION*
- *तरूण भारत संघ - एक प्रयास*
- *अमेरिका कैसे रोक सकता है आतंकवाद*
- *पूर्वोत्तर का आतंकवाद भी पाकिस्तान से जुड़ा है*
- *तालिबान आतंकवादियों की जन्मस्थली*
- *TIDE WILL TURN IN OUR FAVOUR*
- *जाति एवं नस्ल में अन्तर है*

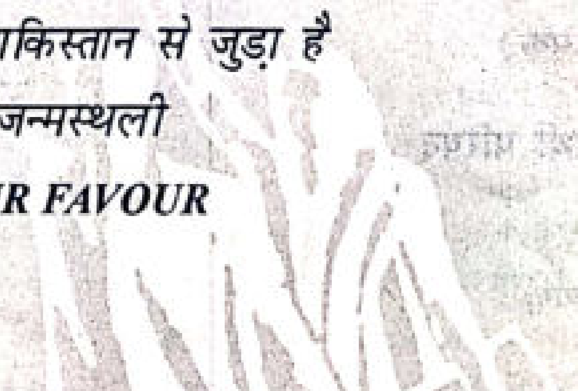

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

दिल्ली प्रदेश

ज्ञान! शील!! एकता!!!

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्

भारत का अग्रमान्य छात्र संगठन जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता को वैश्विक समुदाय में गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त कर एक शक्तिमान, समृद्धशाली एवम् स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में पुनर्निर्माण करने के भव्य लक्ष्य से प्रतिबद्ध है ।

छात्र शक्ति-राष्ट्र शक्ति

॥ वन्दे मातरम् ॥

राष्ट्रीय छात्रशक्ति (द्वैमासिक)
का प्रकाशन
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्
द्वारा
अभाविप कार्यालय
16/3676, रैगरपुरा, करोलबाग,
नई दिल्ली-110005
से किया गया।

संपादक
आशुतोष

मुद्रक
श्रीराम एण्टरप्राइज़ेज
एम-71, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32

राष्ट्रीय छात्रशक्ति (द्वैमासिक) को और अधिक श्रेष्ठ एवं छात्रोपयोगी बनाने हेतु आपके सुझाव एवं सहयोग अपेक्षित हैं। आपके विचार 'संपादक के नाम पत्र' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किये जायेंगे।

भवदीय
संपादक

सम्पादकीय

अमेरिका में विश्व व्यापार केन्द्र एवं पेंटागन पर हुए आतंकी हमलों ने न केवल अमेरिका को झकझोर कर रख दिया है बल्कि विश्व की कूटनीतिक दिशा ही बदल दी है। दुनियां में आतंक का पर्याय बन चुका ओसामा-बिन-लादेन जहां अमेरिका की आंख की किरकिरी बना है वहीं कुछ देशों में वह मसीहा और नायक बनकर उभरा है।

दशकों से कश्मीर में आतंकवाद से जूझ रहे भारत को समस्या के हल के लिए पाकिस्तान के साथ शांतिवार्ता का सुझाव देने वाले और मध्यस्थता के लिये अपनी सेवायें प्रस्तुत करने वाले अमेरिका एवं उसके पिछलगू यूरोपीय देश आतंकवाद के असली चेहरे से सामना होते ही हतप्रभ हो गये हैं। बुश और लादेन के 25 वर्ष पुराने पारिवारिक और व्यावसायिक संबंधों के खुलासे ने अमेरिका को सरेआम नंगा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर अपनी बादशाहत बनाये रखने के लिये पैदा किये गये भस्मासुर अब अपने मालिकों को ही चुनौती दे रहे हैं। न सिर्फ अमेरिका, बल्कि पाकिस्तान और उस जैसे तमाम देशों के लिये यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सबक है।

पूरा भारत आज आतंकवाद से किसी न किसी रूप में प्रभावित है। कश्मीर के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी आतंकवाद के घाव के निशान अभी ताजा हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में चल रहे अलगाववादी आन्दोलनों के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है। पूरे देश में जगह-जगह पर जारी आई.एस.आई. की गतिविधियों एवं 'सिमी' जैसे राष्ट्रघाती संगठनों की गतिविधियां देश की कानून-व्यवस्था के लिये सिरदर्द बन चुके हैं। पाकिस्तान की धरती पर चल रहे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों का सारा उत्पादन भारत में धकेल दिया जाता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति भारत की धरती पर उन्हें जेहादी होने का प्रमाण-पत्र देते हैं और अपनी जरूरतों के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर लगे प्रतिबंध उठा लेता है, कर्जा देता है। संक्षेप में यह एक ऐसी परिस्थिति बनी है जब भारत को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक फैसला लेना होगा।

गत माह देश के अनेक विश्व विद्यालयों, महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव हुए जिनमें अधिकांश स्थानों पर अभाविप ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। विशेषकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर, जहां पर पहली बार परिषद् ने सभी पदों पर जीत हासिल कर केसरिया फहराया है। विजेता प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामना के साथ ही हम सबकी यह अपेक्षा रहेगी कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनमें जताये गये विश्वास को पूरा करने में सक्षम सिद्ध होंगे।

OBITUARY OF GOWRI SHANKARJEE

Janamanchi Gowri Shankar, the man who inspired hundreds of karyakartas and taught organisational science for the last two decades to the ABVP karyakartas throughout the country passed away on 17th July, 11.40 PM at Prashanth Ayurvedic campus Bangalore. Sri J.Gowri Shankar, All India Joint Organising Secretary of Akhil Bharathiya Vidyarthi Parishad (ABVP) was suffering from illness for the last six months. He was suffering with multiple diseses, including diabetes, blood-pressure, kidney malfunctioning, paralysis etc., for last several months. He was admitted to hospital in Bangalore on 29th Jan, 2001. Due to continuous treatment and medical care, his condition was improving slowly in recent days. But unfortunately, on 16th July, 2001 sugar level shot up, kidney functioning deteriorated and breathing problem was there. Finally, the end came due to renal failure and cardiac arrest. He could not be saved.

As per the wish of Gowri Shankarjee and also of karyakartas of Andhra Pradesh, the dead body was brought to Hyderabad on 18th July at 2.00 PM, by Prof. P.V.Krishna Bhat (Former National president) and Sri K.N. Raghunandan (National Secretary). The body was kept at Keshava Nilayam (Sangha karyalaya), for paying last respects and public homage. A condolence meeting was held at 5.30 PM. Prof. Bal Apte, Shri Dattatreya Hosabale, Prof. P.V.Krishna Bhat, Kshetriya Sangha Chalak Justice Parvata Rao, Kshetriya Pracharak Manya Rambhav Haldekarjee, Saha Kshetriya Pracharak Shri Bhagaiah, Shri V.Rama Rao BJP All Inida vice president and many others paid their homage to the Gowri Jee. Shri Muraleedharan, Vice Chairman NYK, Prof. P.Subbaiah, All India Vice-president, ABVP, B.Surendra, South Zone Org. Sec, ABVP large number of workers of A.P and also of various organisations were present and paid their last respects. Mother, sister-in law, younger brother and 3 sisters of Gowri Shankarjee were also present. The funeral started at 7.45 PM and cremation started took place at 10.15 PM.

Though he was on bed and not able to talk much, his memory power never came down. He was alert always and very much cooperative to doctors. He used to recognise people immediately and starts to talk their personal matters and their units organisational matters. Whoever visits him were awe struck with his affectionate talk and memory power. Many people including P.P. Sarsanghachalak Sri K.S. Sudarshanji, Sangha senior Adhikari's Union ministers, Office bearers of various organisations, Karyakarta families visited Gowrijee during this six months period.

Shri Gowrishankarjee was born on 15.12.1949 at Kovur, Nellore district of Andhra Pradesh. At present his mother resides in his kovur house. Gowrijee was the second son among the seven children (3 brothers and 4 sisters). He has lost his father, elder brother and elder sister. Since his childhood he became active in Sangha. He became Parcharak at the end of 1969 after completion of his Diploma in Electrical engineering. First he was sent to Bapatla (Guntur Dist.) as town pracharak. Afterwards he worked as a pracharak at Tenali, Guntur, Eluru and in Ananthapur as Zilla Pracharak. During emergency period he has organised underground movement very effetively in Ananthapur district. Due to his organisational skills, relations with Swayamsevaks family members and grassroots communications, he could build up a strong movement against emergency in that district. He came to ABVP field in June 1979 as full time worker.

He held different responsibilities in ABVP. He was the State organising secretary for Andhra Pradesh (1979-89). Besides A.P he has assigned Orissa state work upto 1991-98 he was the south zone organising secretary. He became All India Joint Organising Secretary in our golden jubilee conference in December 1998. Though his health was not much cooperating with him, he used to tour. His last tour was to Raipur. After the Raipur conference he came to Bangalore for medical treatment. He always wished to work in the field till his last breath. As per his wish only his body has brought on 18th July from Bangaolore to Hyderabad, his head quarter which it left on Jan 3rd

Remaining part on page - 21

एस एफ आई के किले पर लहराया केसरिया

हिमाचल प्रदेश के अधिकांश कॉलेजों में अभाविप का छात्रसंघ पर कब्जा

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की केन्द्रीय छात्र परिषद् के चुनाव में सभी चारों पदों पर जीत दर्ज कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने विश्वविद्यालय पर केसरिया झण्डा फहराने में सफलता हासिल की है। सर्वश्री नरेन्द्र अत्री अध्यक्ष, सुदर्शन सांख्यान उपाध्यक्ष, विक्रम बांशद् महासचिव एवं शशिकांत सहसचिव पद पर चुने गये।

विश्वविद्यालय परिसर एवं मंडी महाविद्यालय राज्य में एस एफ आई के दो मजबूत गढ़ थे जो इस बार के छात्रसंघ चुनावों में विद्यार्थियों द्वारा नकार दिये जाने से ढह गये। यह पहला अवसर है जब अभाविप ने प्रदेश के सबसे पुराने कॉलेजों में मंडी स्थित राजकीय वल्लभ स्नाकोत्तर महाविद्यालय में चारों सीटों पर कब्जा कर एस.एफ.आई. गढ़ को एक तरह से ध्वस्त कर डाला।

हमीरपुर महाविद्यालय की केन्द्रीय छात्र परिषद् में परिषद् का वर्चस्व स्थापित करते हुए प्रधान पद पर अजय कुमार, उपप्रधान पद पर आशीष कुमार, महासचिव पर पंकज ठाकुर एवं सहसचिव पद पर विकास शर्मा ने विजय प्राप्त की। कक्षा प्रतिनिधियों के 26 पदों पर परिषद् के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। दौलतपुर चौक कॉलेज में विद्यार्थी परिषद् ने एन.एस.यू.आई. का पूरी तरह सूपड़ा साफ करके सभी चारों पदों पर जीत का परचम लहराया वहीं पालमपुर के तीनों महाविद्यालयों के अध्यक्ष पद पर अभाविप का दबदबा बना रहा। सनातन धर्म महाविद्यालय राजपुर एवं कन्या महाविद्यालय पालमपुर की सभी सीटें हासिल करने में परिषद् सफल रही।

के.एस.बी. कॉलेज, भटोली में विद्यार्थी परिषद् के प्रत्याशी प्रधान पद के लिये देवेन्द्र कुमार, उपाध्यक्ष नरेश कुमार, महासचिव विशाल सहोड़ तथा सहसचिव पद पर विद्यार्थी परिषद् की ही ज्योति शर्मा भारी मतों से विजयी हुई हैं। कॉलेज के बीस कक्षा प्रतिनिधियों में से 17 परिषद् ने जीते हैं। नालागढ़ कॉलेज के चुनावों में अभाविप ने संयुक्त मोर्चा गठबंधन का सफाया कर दिया। अध्यक्ष पद पर सुरेन्द्र पाल, उपाध्यक्ष राजेश, महासचिव कुलभूषण एवं संयुक्त सचिव हरदीप चुने गये। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय नेरवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने एस.एफ.आई. का सूपड़ा साफ करते हुए सभी पदों पर जबरदस्त जीत हासिल की।

विद्यार्थी समुदाय में राष्ट्रवादी विचारधारा की लहर का असर महाविद्यालयों के चुनावों में भी दिखाई दिया। कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठनों की तुलना में विद्यार्थी परिषद् के प्रत्याशी जीते। छात्र-छात्राओं ने एस.एफ.आई की हत्या और हिंसा की राजनीति का करारा जवाब दिया।

विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों का इतिहास दो दशक से भी ज्यादा पुराना है। यह पहला मौका है जब विद्यार्थी परिषद् ने चारों स्थानों (सीटों) पर जीत दर्ज की है। इससे पूर्व 1983 में जगत प्रकाश नड्डा विद्यार्थी परिषद् प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष चुने गए थे। तब एस.एफ.आई. प्रत्याशी इन्द्र राणा भी बराबर मत मिलने के कारण नड्डा व राणा छह-छह महीने के लिए अध्यक्ष बने थे। 1991 में विद्यार्थी परिषद् ने अध्यक्ष पद को छोड़कर बाकी तीनों सीटें जीत ली थीं। 1978 से लेकर गत वर्ष तक एस.एफ.आई. का जबरदस्त दबदबा बना हुआ था। वर्ष 1995 में विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता कुलदीप ढडवालिया की जघन्य हत्या के बाद से पांच वर्ष तक चुनावों पर रोक लगी रही। यह हत्या एस.एफ.आई. के गुंडों ने की थी। एस.एफ.आई. के नेताओं ने 1978 में एक छात्र सुरेश सूद की हत्या की थी। फिर इसी संगठन के नेताओं ने 1978 व 1988 में क्रम से भारत भूषण और नासीन खान की हत्या कर विश्वविद्यालय परिसर को खूनी राजनीति का अड्डा बना दिया था। ये दोनों एन.एस.यू.आई. के कार्यकर्ता थे।

मंडी महाविद्यालय में 1985 के बाद चारों सीटों पर विद्यार्थी परिषद् को कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। वहां भी एस.एफ.आई. हावी थी। इस बार मार्क्सवादियों को धूल चटाकर विद्यार्थी परिषद् के महेन्द्र-अध्यक्ष, अमित-उपाध्यक्ष, चूड़ामणि-महासचिव पाल वर्मा सहसचिव चुने गए। प्रदेश भर के कुल 56 महाविद्यालयों में से 21 (इक्कीस) में विद्यार्थी परिषद् चारों पदों पर विजयी रही। प्रदेश भर में छात्र संघ चुनावों में विद्यार्थी परिषद् ने 112 सीटें प्राप्त की। एस.एफ.आई. ने 49 और एन.एस.यू.आई. ने 40 सीटें

हासिल की।

विद्यार्थी परिषद् का मानना है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक जीत का कारण छात्र-हितों के लिए लगातार किए गए संघर्ष और रचनात्मक कार्यों का परिणाम है। हमारा मानना है कि पांच वर्ष तक चुनावों पर लगी रोक भी परिषद् के आन्दोलन के कारण पिछले वर्ष हटी थी और विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकार बहाल हुए थे। परिषद् ने विद्यार्थी हित के मुद्दों पर कभी कोई समझौता नहीं किया, चाहे राज्य में सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का मानना है कि विद्यार्थी समुदाय एस.एफ.आई. की खूनी राजनीति से तंग आ गया है। एस.एफ.आई. के आधा-दर्जन से ज्यादा नेताओं को हत्या या ऐसे ही गंभीर मामले विचाराधीन हैं विद्यार्थी परिषद् प्रदेश में रक्तदान करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। प्रदेश भर में वृक्षारोपण, पुस्तक बैंक, सामाजिक बुराईयों के विरूद्ध अभियान व अन्य रचनात्मक कार्य करने वाले समाजिक संगठन के रूप में भी पहचान बनी है।

काशी विद्यापीठ में अध्यक्ष जीता

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के अध्य क्ष पद के प्रत्याशी श्री संदीप सिंह पिंटू ने विजय प्राप्त की। महामंत्री पद पर भी परिषद् समर्थित प्रत्याशी सुधीर सिंह संगम विजयी रहे। गत अनेक वर्षों से काशी विद्यापीठ पर समाजवादियों का कब्जा बना हुआ था।

वाराणसी के ही एक अन्य प्रतिष्ठित महाविद्यालय उदय प्रताप कॉलेज में भी परिषद् समर्थित प्रत्याशी अविनाश कुमार सिंह ने अध्यक्ष पद पर जीत कर परिषद् का विजय अभियान आगे बढ़ाया है।

राजस्थान में छात्रसंघ चुनावों में सफलता

राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सम्पन्न हुए छात्रसंघ चुनावों में सबसे आगे रहते हुए विद्यार्थी परिषद् ने महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर में जहाँ चारों पदों पर अपनी जीत दर्ज की वहीं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर तथा कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में अध्यक्ष पद सहित तीन-तीन पदों पर सफलता हासिल की।

परिषद ने प्रदेश में 95 महाविद्यालयों में चुनाव लड़ा था जिनमें 48 महाविद्यालयों में अध्यक्ष पद सहित कुल 150 पदों पर विजयी हुए । उदयपुर व जयपुर विश्वविद्यालयों में संगठन को हार का मुंह देखना पड़ा। गत वर्ष राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और अधिकांश महाविद्यालयों में छात्रसंघों में परिषद् ने विजय प्राप्त की थी। इस ऐतिहासिक जीत के बाद छात्रसंघों में व्याप्त अव्यवस्था और व्यावसायिक राजनीति को दूर करने हेतु आदर्श छात्रसंघ चुनाव व्यवस्था, चुनाव आचार संहिता और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की आधारभूत योग्यताओं संबंधी एक प्रारूप इन छात्रसंघों के माध्यम से तैयार किया था और राज्य सरकार से इसे सम्पूर्ण प्रदेश में लागू करवाने का प्रयास भी किया। सरकार ने भी इसे लागू करने की मंशा अवश्य जाहिर की परन्तु अपनी कुटिल राजनीति के चलते इसे लागू नहीं किया।

इस बार हुए चुनावों में राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने सत्ता और प्रशासन का एन.एस.यू.आई. के पक्ष में जमकर दुरूपयोग किया एवं कदाचार की सभी सीमाओं को लाँघते हुए सरकारी संरक्षण में फर्जी मतदान तक का सहारा लिया गया। एक प्रकार से यह चुनाव विद्यार्थी परिषद् और राज्य सरकार के बीच लड़ा गया जिसमें सरकार को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा।

महाकौशल में परिषद् प्रत्याशियों की भारी जीत

प्रदेश के 120 महाविद्यालयों में संपन्न हुए छात्रसंघ चुनावों में परिषद् ने उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए 57 स्थानों पर अध्यक्ष पद सहित कुल 237 पदों पर विजय प्राप्त की।

गोआ विश्वविद्यालय में शानदार सफलता

विश्वविद्यालय छात्रसंघ के लिए कुल 9 पदों पर हुए चुनावों में से 7 पदों पर परिषद् प्रत्याशियों की विजय के साथ ही एक बार पुनः अभाविप का वर्चस्व सिद्ध हो गया है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के समय ही छात्रसंघ चुनावों में परिषद् विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करती रही है।

इस वर्ष के लिये चुने गये छात्रसंघ में चेअरमैन श्री राजेन्द्र वर्वे, सचिव परेश देसाई, महिला प्रतिनिधि सुश्री फ्रांसियल रिबेलो तथा चार सदस्य चुने गये।

This is the time to constitute the *NATIONAL EDUCATION COMISSION*

When the British introduced their system of education, the decline of education began in Bharat in all its aspects. The product coming out of our educational institutions are totally alienated from the roots - the family, the society and the nation on the one hand and the agriculture, the business, the industry and other professional activities on the other hand. Culturally and professionally they are misfits.

It was the common view of the participants of the All India Workshop on Education organised by Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad held on Sept. 30 Oct. 1 & 2 2001 in Mumbai. More than 180 participants from various places of the country shows their deep concern with the educational issues and the emerging trens in education.

They feels that many Reform Committees/ Commissions have made many suggestions and a few of them have been implemented but in course of time remedy became worse than the malady. At present, we are at the educaiton system seems to uproot the unity of purpose.

We have accepted the democratic polity even though there is no democratic functioning in many institutions including the educaitonal institutions. It is in this context that we have to analyse the arms of governance in a democratic polity. The most important arms are the judiciary and the civil administration and to a lesser extent, the election commission. These arms maintain the continuity of the national governance irrespective of the changing face of the political power. By and large, they are not influenced by the politics.

Unfortunately, the most important factor in national reconstruction, viz., education is undergoing a constant threat of disintegration. There is no philsophy, which is accepted by the nation, as is the case with judiciary or civil administration. There is thus no scope for continuity in planning and excution of educational policies. It is time then that a permanent Educational Commission is thought of to evolve time tested philosophy, timely policy and methodology of implementation. This Education Commission should thus become an arm of governance just like the judiciary and the civil administration.

Prof. J.L. Azad, former Chief of Education Division, Planning Commission and University Professor of Education said that the Education Commission (1964-66) and the National Policy on Education (1986) had laid down that the investment on education should be gradually increased to reach a level of expenditure of six percent of the national income as early as possible. Except for repeating this suggestion in the plan documents as also in the successive National Policies of Education, the goal has remained a distant dream.

It would also be seen that in the allocation of resources, general higher education is the worst victim. From a measly proportion of 9 percent in the first plan, it appropriated about one fourth of the outlay in the fourth plan. Thereafter, there has been a steep decline in its fortunes; with eighth plan allocations registering an allocation of 8 percent. One does not know whether this sharp decline in the allocation for higher education is a prelude to privatization of higher education or it reflects a disenchantment with the ever increasing body of unemployed and unemployable graduates which most of our universities are churning out year after year. Judged by any yardstick, the down gradation of higher education in the allotment of resorces does not augur well for the educational system.

It has been noted that the Central Government has been investing proportionately lesser amount in the development of educational programs. In the first plan, the central outlay was 4.4% of the total outlay for central programs. In the sixth plan, the proportion was reduce of half i.e. 2.2 percent. In the eighth plan, it has further

improved to 3.3 percent. The figure is however, far short of the position in the first plan.

In India, the New Economic Policy launched in 1990's with its accents on economic liberalization, decentralization, decontrol foreign equity participation and privatization has, among other things, put the seal of acceptability on privatizational of education as also of higher education. A logical corollry of the new economic policy could be the dismmeulling of the state machinery for the administration, financing and regulation of educational institutions. To be specefic, it would allow the market forces to determine the size of student enrolment, the establishment of new instutions and the expansion of existing instutions, determining the curricula and methods of teaching and laying down the amount of cost recovery from the students besides tapping other sources of revenue. In fact, it would mean leaving the field primarily to private bodies.

In view of the fact that the Government has a constitutional responsibility to provide for free and compulsory education to children up to the age of 14. It is difficult to visualize a situation, in which this sector will be handed over to private sector. It is only in the case of secondary and higher education that privatization can be considered.

Before accepting the proposal to introduce complete privatization of education or to allow private universities, we have to think that the privatization, based on differential demand, may be at the cost of national goals. The basic reserch will suffer and dependence on public contributions, mainly fees, may lead to undue burden on students, quite a few of whom may come from the weaker section of society. Alternatively, it may introduce a system of cheaper but low quality education. In market driven demand for courses, 'soft' subjects like History, Archaeology, Music, Languages etc. also may be neglected.

According to Gareth williams, the state should not abdicate its responsibility of financing and managing higher education for the following reasons:

(a) To help ensure that all students are fairly treated.

(b) To help avoid waste of talent.

(c) To share the investment risks between those for whom it proves to be a good investment.

(d) To enable society as a whole to benefit from the external benefits of having a significant number of its members educated to higher levels and

(e) Toencourage universities and colleges to pursue national policy priorities that might have less importance for any of other stakeholders.

The problem is multi-facted and since the future of millions of students and the destiny of the nation is involved, it is necessary that we should tread cautiously. The conclusion that could be drawn is that while we should encourage private participation in administration and financing of higher education, we should not hand over higher education to private parties completely. It is genuinely feared that, for a quite a few, profiteering may be the prime consideration. Further, higher education may have a skewed development in that primarily the market driven courses of study may be provided to the utter neglect of subjects, which have no immediate employment possibilities and yet are important for the socio-cultural development of the country. Education including higher education is far too serous a subject to be left in the hands of private bodies only.

Various issues and aspects of education, like Stucture of Education in India, Self Financing of Higher Education, the role of Private Institutions, Autonomous Colleges, Restructuring of Courses, New trends in higher Education, Private and Foreign Universities, Information technology and The Debate on Saffronisation of Education etc. were discussed in the workshop which was concluded with a brain storming session.

विद्यार्थी संगठन एवं छात्रसंघ

समाज की शिक्षा व्यवस्था के दो उद्देश्य होते हैं। पहला साक्षरता बढ़ाना, उपलब्ध सूचनाओं और ज्ञान को नई पीढ़ी तक विस्तारित करना तथा शोध कार्यों द्वारा नये अन्वेषण करना एवं दूसरा अपने युवा सदस्यों के व्यक्तित्व का विकास करना, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, उनके चरित्र का निर्माण एवं उन्हें एक अच्छा नागरिक और मनुष्य बनाना।

शिक्षा क्षेत्र के प्रशासकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य स्वस्थ संवाद एवं सहयोग के द्वारा यह उद्देश्य प्राप्त किये जा सकते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विद्यार्थी शिक्षा व्यवस्था की धुरी है और उसके लिए ही इस व्यवस्था का निर्माण किया गया है। यह स्वीकार करना कठिन नहीं है कि इस व्यवस्था की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इसमें विद्यार्थी की रुचि एवं सहभागिता परन्तु सामान्यतः विद्यार्थी स्वयं को इस समूची प्रक्रिया से बाहर अंतिम सिरे पर खड़ा पाता है। ऐसे में इस व्यवस्था के प्रति विद्यार्थी का विश्वास एवं स्वस्थ प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिये प्रशासकों व शिक्षकों की ओर से समुचित सावधानी एवं प्रयत्न आवश्यक हो जाते हैं। यह सावधानी तब और आवश्यक हो जाती है जब विद्यार्थी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला है अर्थात् वयस्क है और युवा वर्ग में शामिल है। स्वाभाविक ही युवाओं एवं वयस्कों के साथ बच्चों से पृथक व्यवहार अपेक्षित है।

उपरोक्त पार्श्वभूमि में विद्यार्थी संगठनों एवं छात्रसंघों की भूमिका, उपयोगिता एवं महत्व को स्वीकार किया जाना चाहिए। कोई शिक्षा व्यवस्था अथवा संस्थान संगठनों अथवा छात्रसंघों को छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में अथवा स्वयं छात्र समुदाय के रूप में यथेष्ट अवसर प्रदान कर लाभ उठा सकता है। समाज के विभिन्न सदस्यों एवं वर्गों के बीच प्रत्यक्ष कोई अंतःक्रिया, संवाद अथवा सहयोग हो सकने की तुलना में उनके प्रतिनिधियों तथा संगठनों के माध्यम से अधिक बेहतर ढंग से स्थापित हो सकता है।

विद्यार्थी संगठनों एवं छात्रसंघों के संबंध में अक्सर एक टिप्पणी सुनी जाती है कि वे राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करते हैं एवं शिक्षण संस्थानों के लिये लाभकारी तत्व से अधिक बाधा हैं। इस प्रकार की टिप्पणी सामूहिक कार्य संपादन एवं सहजीवन की महत्ता की समझ कम होने एवं दोषदर्शन की प्रवृत्ति का सूचक है। निस्संदेह, अनेक विद्यार्थी संगठन राजनैतिक दलों के अंश के रूप में कार्य करते हैं, अनेक छात्रनेता किसी न किसी विचार से जुड़े होते हैं और अनेक बार ये संगठन और नेता गैरजिम्मेदार व्यवहार करते हैं। लेकिन क्या इसका अर्थ है कि बिना संगठनों और छात्रसंघों के बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। क्या ये दोषदर्शक रोगी का उपचार उसकी हत्या के रूप में नहीं सुझा रहे हैं।

दोषदर्शी, रोमानी एवं दुराग्रही विचारक की दृष्टि में उपरोक्त प्रकार का सरलीकरण हो सकता है परन्तु सामाजिक गतिजता को समझने और उसके अनुरूप सार्थक कार्ययोजना बनाने के लिये व्यक्ति से अधिक सावधान और धैर्यवान होना अपेक्षित है।

सर्वप्रथम हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम किस प्रकार की समाज रचना में रहना चाहते हैं। जनतांत्रिक अथवा सर्वसत्तावादी। यहाँ पुनः दोषदर्शी लोग जनतंत्र के दोषों को गिना सकते हैं तथा परोपकारी राजाओं एवं जन हितैषी तानाशाहों के उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

अपनी कमजोरियों और अन्य समस्याओं के बावजूद जनतंत्र सामूहिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ अथवा न्यूनतम हानिकर स्वरूप है। यह आवेगों को आत्मसात करने, पराकाष्ठाओं का शमन करने, अंतर्विरोधों को हल करने एवं सहजीवन के लिये संभव सर्वोत्तम कार्यरचना प्रस्तुत करने में सक्षम है।

गणतंत्र एक कला है, मनोदशा है, जीवनपद्धति है तथा एक व्यवस्था है जो समाज को किसी एक व्यक्ति की सनक, रुचि और दृष्टिकोण का शिकार होने से बचाती है। यह व्यक्ति को सामाजिक जीवन के व्यापक संदर्भ में सोचने एवं व्यवहार करने के लिये प्रेरित एवं विवश करती है। लोकतंत्र का त्याग Cure worse than the desease है। इसे त्यागने के स्थान पर इसके नकारात्मक पहलुओं से बचाये जाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र इसी से परिपक्व होता है। पश्चिमी जगत के परिपक्व लोकतंत्रों ने वर्तमान अवस्था तक पहुँचने में लम्बा समय लिया है।

जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहना चाहते हैं तो स्वयंसेवी एवं गैर-सरकारी सामाजिक संगठनों के महत्व को अनदेखा नहीं कर सकते। इस प्रकार के संगठन वह आधार भूमि तैयार करते हैं जिस पर लोकतांत्रिक समाज का ढांचा खड़ा होता है। संविधान और कानून, उनके अंतर्गत निर्मित संस्थापनाएँ, मताधिकार, निर्वाचित निकाय एवं सरकार आदि सरकार के न्यूनतम अंग हैं। वे केवल एक शरीर की भाँति काम करते हैं परन्तु इस शरीर को जीवन राजनैतिक व अन्य समूहों एवं संगठनों—जो समाज में विवेक शक्ति एवं प्रहरी की भूमिका निभाते हैं – के द्वारा मिलता है।

जब कोई संगठनों के महत्व की बात करता है तो वह अवांछित, गैरजिम्मेदार एवं विध्वंसक संगठनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसे संगठन समाज में बहुधा पाये जाते हैं किन्तु समाज उनसे निपटने के मार्ग ढूंढ़ निकालता है। या तो कानून के द्वारा उन पर नजर रखी जाती है अथवा वांछित, उत्तरदायी एवं रचनात्मक संगठनों द्वारा।

व्यापक समाज में जो महत्व संगठनों का होता है, शिक्षा क्षेत्र में वही महत्व विद्यार्थी संगठनों का है। वे छात्रों को नेतृत्व प्रदान करते हैं, उनकी अभिलाषाओं को व्यक्त करते हैं, उनके हितों का ध्यान रखते हैं तथा उनके न्यायसंगत अधिकारों के लिये संघर्ष करते हैं और एक विवेकपूर्ण सामाजिक संगठन के नाते उन्हें उनके कर्तव्यों का भी स्मरण कराते हैं।

छात्र संगठन बहुधा उनकी राजनैतिक संबद्धता के कारण आलोचना के पात्र बनते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने स्वयं को विचारपूर्वक दलगत राजनीति से ऊपर रखा है परन्तु इसमें अन्य संगठनों की क्षुद्रता सिद्ध करने का भाव नहीं है। समाज में राजनीति और राजनैतिक दल होना न तो गलत है और न ही अवांछनीय। इसके विपरीत लोकतांत्रिक समाज में वे आवश्यक उपकरण हैं। यहाँ वास्तविक और अवास्तविक राजनीति के मध्य विवेक रखना होगा। अनेक बार कोई राजनेता अपेक्षित मापदंडों पर खरा नहीं साबित होता, यह सर्वथा भिन्न स्थिति है।

यह अत्यंत स्वाभाविक है कि कोई दल समाज के विभिन्न भागों से अपने सदस्यों की भर्ती करे। दल के लिये यह भी स्वाभाविक है कि उसके विभिन्न प्रकोष्ठ हों। यदि कोई दल विद्यार्थियों, विशेषकर वे विद्यार्थी जो मतदाता बन चुके हैं, के बीच भी अगर अपने सदस्य बनाना चाहता है तो यह आपत्तिजनक नहीं हो सकता। जहाँ तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का प्रश्न है, उसकी आपत्ति राजनेताओं और राजनीतिक दलों को सामाजिक सक्रियता का एकमात्र स्रोत अथवा नियंता मान लिये जाने पर है। विरोध है राजनीति, राजनेताओं एवं राज्य के तंत्र द्वारा प्रत्येक सामाजिक गतिविधि में हस्तक्षेप एवं उसकी सर्वव्यापकता का। अभाविप सामाजिक संगठनों की स्वायत्तता की समर्थक है तथा विश्वास करती है कि लोकतंत्र में विभिन्न स्वतंत्र संगठनों का अस्तित्व है और होना चाहिए।

जहाँ तक छात्रसंघों की बात है, वे युवा-नागरिकों को लोकतांत्रिक पद्धति का प्रथम अभ्यास कराने का महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करते हैं। छात्रसंघ के माध्यम से विद्यार्थी सामूहिक निर्णय करने तथा सामूहिक हितों एवं अभिलाषाओं को पूरा करने का पाठ सीखते हैं। छात्र समुदाय की अपेक्षाओं और माँगों को प्रकट करने के माध्यम तथा उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये एक हथियार के रूप में तथा उनके कल्याण के लिये गतिविधियाँ आयोजित करने के लिये छात्रसंघ एक मंच बनता है। सुसंगठित एवं प्रेरणायुक्त छात्रसंघ युवा-छात्रों की ऊर्जा को सामाजिक एवं राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में नियोजन का उपयोगी एवं प्रभावी माध्यम बन सकता है।

यदि विद्यार्थी संगठनों और छात्रसंघों को अलग रखा गया तो शैक्षिक ढांचा अधूरा रहेगा एवं अपने उद्देश्य पूर्ण करने में असफल सिद्ध होगा।

—राजकुमार भाटिया

हम संघर्ष करेंगे : नकुल भारद्वाज

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर विजयी हुए श्री नकुल भारद्वाज छात्रसंघ में परिषद के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। डी.ए.वी. स्नाकोत्तर महाविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष रह चुके श्री भारद्वाज संघर्षशील व मेधावी छात्र हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने केन्द्रीय परिषद् में एक पद तथा कार्यकारी परिषद् में सात पदों पर विजय प्राप्त की है।

यू-स्पेशल बसों की संख्या बढ़ाने, हॉस्टलों के निर्माण की माँग, व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने, शिक्षा के लिए एन.सी.सी. व एन.एस.एस., कॉम्पैक्ट कैंपस बनाने के तथा पेशेवर नेतागिरी खत्म करने जैसे बिन्दुओं वाले परिषद् के घोषणापत्र को लागू कराने के लिए संघर्ष का विश्वास दिलाते हुए वे छात्रसंघ चुनाव में जीत के लिये अपनायी जाने वाले घटिया तौर-तरीकों की तीखी आलोचना करते हैं।

छात्रसंघ का उपयोग राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने की सीढ़ी के रूप में किये जाने का जो क्रम एन.एस.यू.आई. ने गत कुछ वर्षों में अपनाया है उससे छात्रसंघ की गरिमा को चोट पहुँची है। उनका मानना है कि इसे पुनः स्थापित करने के लिए संघर्ष करना होगा जिसके लिए हम तैयार हैं।

छात्रसंघ का उपयोग रचनात्मक कार्यों में भी हो सकता है इसका उदाहरण देते हुए वे बताते हैं कि कॉलेज अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में उड़ीसा एवं गुजरात में प्राकृतिक आपदाएं आईं और दोनों ही बार उन्होंने कॉलेज के छात्रों को साथ लेकर उल्लेखनीय मात्रा में पीड़ितों हेतु सहायता सामग्री का संग्रह किया एवं संगठन के माध्यम से उसे आवश्यकता वाले स्थानों पर भेजा।

कॉलेज स्तर पर क्रिकेट के खिलाड़ी रहे श्री नकुल भारद्वाज दिल्ली विश्वविद्यालय के पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज से स्नातक उत्तीर्ण करने के पश्चात् वर्तमान में दर्शनशास्त्र में एम.ए. के विद्यार्थी हैं।

STRUCTURE OF EDUCATION

The higher education system in India is the largest among the third world nations and the second largest in the world. There are 273 universities comprises 16 central and 42 Deemed Universities and 11,831 affilated colleges with the strength of 3.5 Lac teachers and 8 million students including 3 million girls students.

The system is monitored by **University Grants Commission (UGC)** coordinates, maintains standard and gives grants to university and colleges.

The state governments, under law, are entitled to establish their own universities, funded by the respective state government which provides maintenance as well as development grant to them. The coordination and cooperation between the Union and the States is brought about by the Central Advisory Board of Education (CABE).

The University Grants Commission (UGC) is a statutory organisation established by an act of Parliament in 1956. It monitors, coordinates with the states and helps maintain standard of teaching, examination and research in Higher Education. It disburses grants to universities and colleges, advises Union and State Governments on measures to improve university education and frames rules and regulation for teaching and research. It also frames regulations such as those on the minimum standards of instruction and qualifications of teachers, on the advice of subject specialists and academicians with whom it frequently interacts in connection with formulation, monitoring, and evaluation of programmes. The UGC has no funds of its own. It receives both Plan and Non-Plan grants from the Union Government to carry out the responsibilities assigned to it by law. It allocates and disburses full maintenance and development grants to the Central Universities, the colleges affiliated with Delhi and Banaras Hindu Universities and some 'Deemed Universities. The Universities and colleges established by the state governments do get UGC funds (non-Plan) but for specific programmes or a development scheme.

The Commission consists of the Chairperson and Vice-Chairperson and ten other members appointed by the Central Government. The Chairperson is selected from persons who are not officers of Central Government or of any State Government of the ten other members, two are selected from the officers of the Central Government, not less than four are from persons who are, at the time they are so selected, teachers of universities. The remainder are selected from persons.

(a) Who have knowledge of or experience in agriculture, commerce, forestry or industry,

(b) Who are members of the engineering, legal, Medical or any other learned professions.

(c) Who are vice-chancellors of universities or who, not being teachers of universities, are in opinion of the Central Government, educationists of repute or have obtained high academic distinction.

There are various statutory bodies established by the acts of parliament for various disciplines of studies like AICTE, MCI, NCTE, Bar council of India, Pharmacy Council etc.

The ALL India Council of Technical Education (AICTE) set up under an Act of Parliament, is the statutory body of the Government of India to grant approval to technical/ professional programmes of study in diploma, undergraduate and postgraduate degree level in the field of Engineering and Technology, Pharmacy, Management, Computer Application, Information Technology, Architecture & Town Planning, Hotel Management

and Applied Arts & Crafts.

The Medical Council of India :- A statutory body- was constituted in February, 1934 under an Act of Parliament- the Indian Medical Council Act, 1933. This Act was replaced by Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Some amendments to this Act were made in 1958 (36 of 1958) and in 1964 (24 of 1964).

The National Council for Teacher Education (NCTE) in its previous status since 1973, was an advisory body for the central and State Governments on all matters pertaining to teacher education, with its Secretariat in the Department of Teacher Education of the National Council of Educational Research and Training (NCERT). Despite its commendable work in the academic fields, it could not perform essential regulatory functions, to ensure maintenance of standards in teacher education and preventing proliferation of substandard teacher education institutions. The National Policy on Education (NPE), 1986 and the Programme of Action thereunder, envisaged a National Council for Teacher Education with statutory status and necessary resources as a first step for overhauling the system of teacher education. The main objective of the NCTE is to achieve planned and coordinated development of the teacher education system throughout the country, the regulation and proper maintenance of Norms and Standards in the teacher education system and for matters connected therewith. The mandate given to the NCTE is very broad and covers the whole gamut of teacher education programmes including research and training of equipping them to teach at pre-primary, primary, secondary and senior secondary stages in schools, and non-formal education, part-time education, adult eduction and distance (correspondence) education courses. NCTE has its headquarter at New Delhi and four Regional Committees at Bangalore, Bhopal, Bhubanseshwar and Jaipur to look after its statutory responsibilities.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) is an apex resource organisation registered as a society set up by the Government of India, with headquarters at New Delhi, to assist and advise the Central and State Government on academic matters related to school education.

The NCERT provides academic and technical support for improvement of school education through its constituents.

The National Institute of Eduction (NIE) in New Delhi one of the constituent of NCERT through its various Departments caries out research and development functions related to pedagogical aspects of curriculum, prepares prototype curricular and other supplementary instructional material, develop school education-related database and undertakes experiments in preschool, elementary and secondary stages to nurture allround development of the learner. The NIE also organises in-service training of key resource persons and teacher educators associated with implementation of centrally sponsored school improvement schemes. The Central Institute of Educational media -related research, development, training, production and extension functions, and provides academic and technical guidance and support to the State Institutes of Educational Technology (SIET). Pandit Sunderlal Sharma Central Institute of Vocational Education (PSSCIVE) yet another constituent, located in Bhopal, organises research and development functions related to vocational education in the school sector.

The Field Offices of the NCERT, mostly located in the state capitals, carry out educational liaisoning with Department of Education and other related institutions on problems and issues of school education in the states and apprise them of activities and programmes of the NCERT.

The Indian Council for Agricultural Research (ICAR) is an autonomous apex national organisation registered as a society which plans, conducts and promotes research, education, training and transfer of technology for advancement of

agriculture and allied sciences. The ICAR was set up on 16th July 1929 on the recommendations of the Royal Commission on Agriculture. It was re-organised in 1965, and again in 1973. Over the years it has developed a large research and training infrastructure to work on the production and other emerging problems confronted in agriculture to meet the growing demands for food, fibre and fuel. ICAR acts as a repository of information and provides consultancy on agriculture, horticulture, resource management, animal sciences, agriculture engineering, fisheries, agricultural extension, agricultural education, home science and agricultural communication. It has the mandates to co-ordinate agricultural research and development programmes and develop linkages at national and international level with related organisations to enhance the quality of life of the farming community.

National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA) is a national institution in educational planning and administration in South Asia. An autonomous organization registered under Societies Registration Act of 1860, it is fully funded and sponsored by the Government of India. With specialization in policy, planning and management in education, NIEPA is the professional wing of the Government of India. Its prime concerns are capacity building in educational policy, planning and management through research, training, consultancy and dissemination

NIEPA's origin can be traced back to UNESCO Regional Centre of Educational Planners and Administration. On the completion of the 10- year contract with UNESCO, the Government of India took it over and renamed as National Institute of Educational Planning and Administration in 1979 emphasising on research besides staff development.

The goals of the Institute are:-

(a) Organising training, conferences, workshops, meetings, seminars for Senior educational officers of the Central and State Governments and Union Territories.

(b) Undertaking, aiding, promoting and coordinating research in educational planning and administration.

(c) Providing academic and professional guidance.

(d) Providing consultancy service to State Governments and educational institutions.

(e) Acting as a clearing house of ideas and information

(f) Preparing, printing and publishing papers, periodicals and books on Educational Planning and Administration.

(g) Collaborating with other agencies, institutions and organisations and organisations in India and abroad.

These goals are achieved through Research, Training, Consultancy and Professional Support Service, and Extension and Dissemination Activities. All the activities, focus on educational policy, planning and management covering all levels of education from primary to higher and technical education and adult and non-formal education.

The National council for vocational training (NCVT) an advisory body was set up by the Government of India through a notification in 1956 with the aim of co-ordinating the training programmes in the country, bringing about uniformity of standards and awarding certificates of proficiency in craftsmanship on an All India basis.

The Council has the responsibilities of all academic aspects of Industrial Training Institutes throughout the country including prescribing standards in respect of syllabi, equipment, duration of courses and methods of training. The ITI's and ITC's and throughout the country are affiliated to NCVT who conduct the tests for the students of these institutions.

प्रयास — तरुण भारत संघ

अब सरिस्का वह नहीं है जो गत आठवें दशक में था। सरिस्का आन्दोलन के बाद यह बदला हुआ है। सरिस्का बचाओ आंदोलन लम्बे किन्तु बहुरंगी संघर्षों की गाथा है। तरुण भारत संघ की भागीदारी से सरिस्का के लोगों ने संघर्ष किये। संघर्षों की विधा गांधीवादी दर्शन पर आधारित रही जिसमें ग्राम स्वराज्य के स्वप्न संजोये गये थे। महिला व बाल विकास, लोक शिक्षण, सफाई, सेन्द्रिय खाद कार्यक्रम, अन्न भंडारण, ग्राम कोष, शराब बंदी, आर्थिक संयोजन जैसे कामों को लेकर तरुण भारत संघ ने 1985 में इस क्षेत्र में प्रवेश किया। शीघ्र ही इसका जन-जन से जुड़ाव हुआ। आत्मीयता बढ़ी।

भू-जल संरक्षण, जंगल की रक्षा जंगली जीवों की सुरक्षा, जंगलवासियों की बेदखली रोकने और जमीन खनन के मुद्दों ने क्रमशः संघर्ष शृंखला को जन्म दिया। इसी क्रम में न्याय के लिये कानूनी संघर्ष भी करने पड़े।

संघर्षों में जूझते तरुण भारत संघ को मूल्यवान अनुभव मिले। पारंपरिक तरीकों की अहमियत का अहसास हुआ। सामलाती सोच की ताकत के दर्शन हुए। जंगल, जीव, जल, जंगलवासी और जमीन एक-दूसरे के दोस्त है यह अनुभव हुआ।

देवरी गांव के भंभू 1986 में अपने समधी के साथ तरुण भारत संघ कार्यालय में आये। अपनी व्यथा कही—बड़ी मुश्किल में हैं। कुएं सूखे पड़े है। जबरदस्त जल संकट है। पानी न पीने को है न जानवरों की प्यास बुझाने को। पहाड़ियां नंगी हो चुकी हैं, पेड़ ठूंठ से मुंह बाए खड़े हैं। लोग गांव छोड़ कर जा रहे हैं।

भंभू की व्यथा कथा वहां के जीवन की प्रतिनिधि व्यथा कथा थी। अभिव्यक्ति में पीड़ा थी, व्यवस्था के प्रति आक्रोश था। तरुण भारत संघ के महामंत्री राजेन्द्र सिंह खुद देवरी गये जहां उन्होंने स्थिति और बदतर ही पाई। पर वे निश्चय का भाव लेकर लौटे। चर्चा हुई, सामूहिक निर्णय हुआ कि इस मुद्दे पर काम करना है। भू-जल संरक्षण के मुद्दे पर। बड़े-बूढ़ों से बात हुई तो जोहड़ का विकल्प सामने आया।

कार्यकर्ता स्तर पर चर्चा और गांव वालों से बातचीत के बाद देवरी में सबसे पहले कारोज वाला जोहड़ बनाने का निर्णय हुआ। सामलाती देह की परम्परा को पुनः कायम करने के लिये समुदाय को एक जुट करना था। कार्य चुनौतीपूर्ण था। बिखरों को जोड़ने का था, विरोधियों को सहयोगी बनाना था।

परिश्रम और संवाद के फलस्वरूप एकजुटता बनी और जोहड़ का काम शुरू हुआ। तरुण भारत संघ के कार्यकर्ता व ग्रामीण जन सामलाती सूझ-बूझ व परिश्रम से एकजुट हो काम पर लग गये। देवरी में जोहड़ जुलाई से पहले ही बन चुका था। स्थान चयन से लेकर श्रमदान के काम का भुगतान, समाज के तरीके और साझा निर्णयों से हुए।

जुलाई से वर्षा हुई तो जोहड़ भर गया, आसपास के कुएं रिसाव से सजल हो गये। लोगों के चेहरे चमक उठे। इधर प्रकृति

तरुण भारत संघ के महामंत्री श्री राजेन्द्र सिंह को रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिलने पर अभाविप के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री दत्तात्रेय होसबाले का शुभकामना संदेश

आदरणीय श्री राजेन्द्र सिंह जी,
सप्रेम नमस्कार।

आपको जलसंधारण के अनोखे एवं यशस्वी प्रयास के लिये तथा समुदाय चेतना एवं नेतृत्व के लिये रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा, यह समाचार जानकर अपार हर्ष हुआ। मेरी व अभाविप की ओर से आपका शत्-शत् अभिनन्दन।

अपने तरुण भारत संघ के माध्यम से राजस्थान में जो पुनःचेतना के कार्य किये हैं उससे सारे देश में एक प्रेरणा एवं आशा की ज्योति आपने जलाई है। न केवल किसानों व सूखे का सामना करने वाली जनता को आपने उपाय दिखलाया है बल्कि जनसेवा एवं जनविकास के काम में सक्रिय स्वयंसेवी संस्थाओं के सम्मुख एक सफल उदाहरण भी प्रस्तुत किया है आपके इस काम के बारे में रा. स्व.संघ के सरसंघचालक मा. सुदर्शन जी हमारी बैठकों में कई बार प्रशंसात्मक उल्लेख करते हैं।

भारतीय समाज के रेगिस्तानों में मृगजल दिखाने वालों की संख्या कम नहीं है। उसके विपरीत आप व तरुण भारत संघ वास्तव में भगीरथ प्रयास कर जलसृष्टि किये हैं। आपको प्राप्त यह पुरस्कार इसी प्रकार गंगावतरण के कार्य में मग्न सभी जल संधारण प्रयासी व्यक्ति एवं संस्थाओं का सम्मान है। पुनः एक बार बधाई तथा आगामी योजना के लिए हार्दिक शुभेच्छा।

सभी सहयोगियों को नमस्कार।
आपका
दत्ता होसबाले

की कृपा, उधर परिश्रम के फल से भविष्य की चिन्ता से मुक्ति। गांव छोड़ बैठे लोग लौटने लगे।

1988 में तरुण भारत संघ ने लोगों की साझेदारी से गांवों में अखंड रामायण पाठ आयोजित किये। मकसद था-जंगल और जंगली जीवों को बचाने का। अरावली बचाओ यात्रा का भी आयोजन किया गया। इस सबका प्रभाव सकारात्मक रहा। सरिस्का में बसे गांव वाले जंगल की रक्षा के लिये कटिबद्ध हो गये। दस्तूर तय हो गये, उनकी पालना हुई—

- अंगूठे से मोटी लकड़ी नहीं काटेंगे।
- कुल्हाड़ा लेकर जो जंगल जायेगा, दंड का भागी होगा।
- जंगल व जल संरक्षण के लिये साझा काम करेंगे।
- सामलाती चीजों का संवर्धन मिलकर करेंगे।
- बाहरी हमलों का मिल कर सामना करेंगे, उन्हें रोकेंगे
- ग्राम सभा के मार्फत गांवाई निर्णय होंगे।

इन सबका सामूहिक प्रभाव वनकर्मियों पर पड़ा। नब्बे के दशक में उनके रिश्ते ग्रामीणों से सुधरे। वे एक-दूसरे की मदद को आने लगे। समरसता की स्थिति बनी।

प्रारंभिक सोच थी कि खनन से पर्यावरण का नुकसान जरूर होता है किन्तु काफी लोगों को रोजगार भी मिलता है। राष्ट्र के विकास के लिये पूंजी भी मिलती है। किन्तु जब 1986 में अलवर के गांवों में जल, जंगल व जमीन के संरक्षण का काम शुरू किया तो खनन कार्य से पैदा हुई समस्याओं का अहसास हुआ। कार्यकर्ताओं ने जमुआरामगढ़ के जंगलों को कटते देखा, करौली में लाल पत्थरों की खदानों में मजदूरों को लालिमा खोते देखा, पत्थर कुटाई व घिसाई करते लोगों को पिसते-छीजते देखा। तीन वर्षों तक किये गये स्वास्थ्य अध्ययनों से मालूम हुआ कि खनन कार्य से जुड़े मजदूरों में से 37 प्रतिशत मजदूर असाध्य रोग सिलिकोसिस से पीड़ित थे, 64 प्रतिशत श्वास-खांसी के रोगी थे। 29 प्रतिशत को शरीर दर्द रहता था। इससे बचने के लिये शराब की शरण में जाने की आदत बन गयी थी जो लत के रूप में बदल चुकी थी। खनन से सफेद होते मजदूरों की दशा और दयनीय होती जा रही थी। दूसरी ओर खनन कार्यों के कारण आस-पास के सुंदर जंगल प्रदूषित हो रहे थे। पूरी लगन, साझा प्रयत्नों और परिश्रम से बनाये जोहड़ों से पानी का रिसाव होने लगा। लगा कि यदि इसे नहीं रोका गया तो लोगों की उपलब्धियां खोखली हो जायेंगी। इसके लिए त्रि-आयामी कार्य योजना निश्चित हुई। पहला, खनन मजदूरों को संगठित करना, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराना और उनके बीच जागरण का कार्य करना। दूसरा, खनन कार्यों को रोकने एवं उनके फैलाव को अवरुद्ध करने के उपाय किये जायें और तीसरा, खनन कार्य से मुक्त होने पर उन लोगों को जल, जमीन, जंगल, जोहड़ संबंधी सृजनात्मक कामों में जोड़कर उनकी रोजी रोटी का इन्तजाम किया जाये। इस तरह सेवा कार्यों में एक और आयाम जुड़ गया।

संघर्ष जारी है पर लोगों की समरसता संघर्ष के लिये शक्ति प्रदान कर रही है। जंगलात वाले, जो कभी जंगलवासियों के दुश्मन माने जाते थे, अब दोस्त बनकर उन्हें ताकत दे रहे हैं। सरिस्का में अब संघर्ष और समरसता दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ने इस अभियान में जुड़े कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ़ाया है।

श्री दत्तात्रेय होसबाले के शुभकामना संदेश का श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रेषित पत्रोत्तर

आदरणीय श्री दत्तात्रेय होसबाले जी,

सादर नमस्कार।

आपका सस्नेह पत्र मिला। पत्र पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। आप जानते हैं, यह पुरस्कार भारतीय देश ज्ञान व परम्परा को मिला है। हमने जो कार्य किया है, वह तो हमारे देश के संगठित, देशज, परम्परागत ज्ञान को उभारने-जगाने की विधि को मिला है। हमने तो केवल अपने समाज के अहसास व आभास को जगाया। बस समाज अपने आप काम में जुट गया। फिर हम अपने समाज के साथ बने रहे। समाज कभी-कभी हमें बैसाखी की तरह उपयोग कर लेता है। मैं अपनी तथा तरुण भारत संघ की बस यही भूमिका देखता हूं।

कभी-कभी चिकित्सक बनकर अपने समाज को सलाह-मशविरा देना पड़ता है आगे रहना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छी स्थिति तो बस समाज को दोनों पैरों पर जल्दी से चलाने योग्य बनाकर वहां से हटने की होती है। वही हम कर रहे हैं। अब सैंकड़ों गांवों में हमें जाने की जरूरत नहीं। वे स्वयं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं।

श्रद्धेय श्री मा. सुदर्शन जी का स्नेह भी हमें मिला। वे दो दिन हमारे कार्य क्षेत्र में रहे थे। उन्होंने इस काम को बहुत ही गहराई से देखा था। हम उनके, आप सबके बहुत आभारी है। आपके सबके प्रेम वश ही हम इतना बड़ा काम कर पाये। आगे भी आप सबका प्रेम बना रहेगा।

आपका

राजेन्द्र सिंह

अमेरिका कैसे रोक सकता है आतंकवाद?

–डॉ. बलराम मिश्र

विश्व का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो आतंकवाद के भूत से प्रभावित न हो। आश्चर्य का विषय यह है कि विश्व की कई बड़ी सरकारें, कई बड़े नेता एवं जाने-माने लोग भी इतना सहमे हैं कि वे विभिन्न प्रकार के कुतर्क दे कर इस समस्या का उबाऊ दार्शनिकीकरण करके परोक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन ही करते हैं। परन्तु, यह एक शुभ चिह्न है कि अनेक मूर्धन्य विचारकों ने सत्य को सत्य कहने का आदर्श प्रस्तुत किया है। दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक 'एशियन एज' के 24 सितम्बर, 2001 के अंक में एक आलेख प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक है "दि साफ्ट स्पाट इन यू एस इंटेलीजेंस।" लेखक हैं भारत की गुप्तचर संस्था 'इंटेलिजेंस ब्यूरो' के अवकाश प्राप्त प्रमुख एम.के. नारायणन। तथ्यों के आधार पर वे कहते हैं कि अमेरिका पर दुस्साहसिक आक्रमण के बाद ही पश्चिमी देशों ने आतंकवाद के वीभत्स रूप को पहचानना प्रारम्भ किया है।

11 सितम्बर, 2001 को न्यूयार्क के विश्व व्यापार केन्द्र की दो गगन चुम्बी इमारतों एवं वाशिंगटन में अमरीकी सुरक्षा विभाग के महत्वपूर्ण भवन पेंटागन पर किए गये विध्वंसक आक्रमणों के पीछे अत्यन्त सुनियोजित षड्यंत्र था। टुकड़ों-टुकड़ों में उपलब्ध अनेक साक्ष्यों से स्पष्ट हो चला है कि अमेरिका के तीन हवाई अड्डों, बोस्टन, न्यूयार्क एवं डल्लास से उठाये गये आक्रामक धावों में शामिल आतंकवादियों के गिरोहों में ऐसे शिक्षित पायलट भी थे जो यह जानकारी रखते थे कि किस प्रकार हवाई जहाजों में लगे रेडियो संकेतों के आदान-प्रदान करने वाले यंत्रों को निकम्मा कर दिया जाये। शायद उनको यह भी प्रशिक्षण मिला था कि किस प्रकार काकपिट में लगे वॉइस रिकार्डर को निष्क्रिय किया जाता है। वे सभी विमान अपहर्ता अरब मूल के इस्लामी कट्टरपंथी थे। उन्हें हवाई अड्डों की सुरक्षा संबंधी खामियों की सारी जानकारी पहले से थी इसीलिए वे अपने साथ चाकू एवं कार्डबोर्ड कटर आसानी से ले जा सके थे। एक अपहृत विमान से हुई सेलफोन-वार्ता से यह जाहिर होता है कि विमान अपहर्ता बिन लादेन की संस्था अल-कायदा से जुड़े थे।

संयुक्त राज्य-अमेरिका अनेक वर्षों से विभिन्न प्रकार के आतंकवाद की चपेट में रहा है, परन्तु उसे समूल नष्ट करने की उसकी इच्छा शक्ति कभी नहीं जागी। अमेरिका ने आतंकवाद के अनेक वीभत्स चेहरों को पहचानने में भी उपेक्षा करता रहा। वह कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद से पैदा होने वाले खतरे को भी नहीं भांप सका। अब अमेरिका ने आतंकवाद तथा आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों के विरुद्ध सख्त कार्यवाई करने का संकल्प किया है।

इस कार्य में अमेरिका को सहायता एवं सहयोग देने में सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थिति वाले जो देश हैं वे हैं इजरायल एवं भारत। दोनों ही कई वर्षों से इस्लामी आतंकवाद के शिकार हो रहे हैं। 11 सितम्बर के हत्याकाण्ड के लिये जो इस्लामी आतंकवादी जिम्मेदार हैं वे उस पुराने रूढ़िवादी ढांचे में फिट नहीं बैठते जिसमें पढ़ाकू विश्लेषक एवं मनोवैज्ञानिक उन्हें बैठाना चाहते हैं। वे सुशिक्षित थे। कुछ की तो इंजीनियर एवं वैज्ञानिक होने की व्यावसायिक पृष्ठभूमि थी। अपने कट्टरपंथी विश्वासों, उच्चस्तरीय प्रेरणाओं एवं "पवित्र युद्ध" या जिहाद की लड़ाई में प्राण देने की इच्छा के कारण ही उन्होंने 11 सितम्बर को जघन्य अपराध किया था। इस दुष्कृत्य में तथा मजहबी प्रेरणा प्राप्त दूसरे आतंकवादी गिरोहों में, जैसे हरकत-उल-मुजाहिद्दीन एवं लश्कर-ए-तोयबा जो कि जम्मू-कश्मीर में काम करते हैं। ये सभी, जो कुछ भी गैर इस्लाम है, उससे सख्त नफरत करते हैं।

भारतीय गुप्तचर संस्थाओं, विशेष रूप से इंटेलिजेन्स ब्यूरो के पास इस्लामी आतंकवाद के मूल स्रोतों से सम्बन्धित जानकारियों का खजाना है जो खुफिया तरीकों से या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सूडान एवं अन्य एक दर्जन से भी अधिक इस्लामी देशों के हजारों भाड़े के "जिहादियों" से गहन पूछताछ के बाद जुटाया गया है। इन पूछताछों से इन रिपोर्टों की पुष्टि होती है कि उनके द्वारा अमेरिका के खिलाफ "निर्णायक युद्ध" लड़ा जाना है "क्योंकि उनकी मान्यता है कि वैश्वीकरण एवं पाश्चात्य सिद्धान्त इस्लाम की अन्तरात्मा तथा इस्लामी जीवन पद्धति का हनन कर रहे हैं।" अमेरिकी गुप्तचर संस्थायें इस प्रकार के सूचना खजानों का अध्ययन करके लाभान्वित हो सकती हैं।

अमेरिका की गुप्तचर संस्थायें, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफ.बी.आई.) तथा सेण्ट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सी.आई.ए.) अपनी समकक्षी भारतीय गुप्तचर संस्थाओं के साथ मिल-बैठकर उनके अनुभवों-उपलब्धियों से अपने स्वयं के अनुभवों-उपलब्धियों की यदि तुलना करें तो उन्हें लाभ होगा। अधिकारियों के लिये यह कोई रहस्य नहीं है कि 11 सितम्बर के आतंकवादी वायुयान अपचालकों ने अपनी पहचान छुपाने की जहमत क्यों नहीं उठाई और अपने पीछे खोजबीन सम्बन्धी कुछ पुछल्लों की झलकियां छोड़ गये। जांच-पड़ताल करने वाली संस्थाओं को वे इस बात के लिए बहकाने की कोशिश करते हैं

कि गुत्थी सुलझ गई है। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि परदे के पीछे चल रही अनेक अन्य आतंकवादी गतिविधियां अबाध गति से चलती रहें।

आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सभी देशों के आतंक विरोधी सूचना-संसाधनों के अन्तर्राष्ट्रीय निकाय से काफी लाभ मिल सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में मानवीय खुफिया तंत्र पर भी अधिक से अधिक भरोसा करना चाहिए। लोकतांत्रिक देशों में युनाइटेड किंगडम की एस.आई.एस., इजरायल की गुप्तचर संस्थायें, और भारत की रिसर्च एण्ड अनालिसिस विंग तथा इंटेलिजेंस ब्यूरों ने इस दिशा में पहले से ही काफी कार्य किया है। उन सभी के अमूल्य सहयोग का लाभ उठाया जाना चाहिए। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी सहयोग देने की बात कही है, परन्तु उसके सहयोग को अत्यन्त सावधानी पूर्वक देखना होगा क्योंकि उसकी सशस्त्र सेनाओं तथा गुप्तचर संस्थाओं में कट्टरपंथी तत्वों की गहरी पैठ है। पाकिस्तानी सहयोग की बात एक दुधारी तलवार के समान हो सकती है।

अफगानिस्तान में भारतीय गुप्तचर संस्थाओं के अच्छे खुफिया सूत्र रहे हैं। अफगानी तथा भारतीय खुफिया तंत्रों में, और विशेष रूप से अफगानिस्तान की 'खाड' नामक संस्था से, अच्छे सम्बन्ध थे। अमेरिकी गुप्तचर संस्थाओं को अपने देश में भी झांकना होगा। अमेरिका के अन्दर भी बिन लादेन के संगठन की जड़ें फैली होने की संभावना है। आतंकवादी अभियान में सामने दिखने वाले आतंकियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण वे दिग्गज लोग हैं जो आतंकवादी योजनायें बनाते हैं। केवल एक लादेन ही क्यों, कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन पर हुई 1993 की बमबारी से सम्बन्धित फाइलों के पुनः अवलोकन से भी लाभ मिल सकता है।

अमेरिका के खुफिया तंत्र के सूचना संग्रह विभाग का भी एक अन्धापन है कि वे अपने मित्र खुफिया तंत्रों की बात नहीं सुनना चाहते और उनके द्वारा की गई चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते। इस वर्ष के प्रारम्भ में ओसामा बिन लादेन के लन्दन स्थित एक प्रमुख समर्थक के घर से आतंकवाद से प्रशिक्षण देने सम्बन्धी जानकारी देने वाली एक पुस्तक पकड़ी गई। इस पुस्तक में आतंकवाद फैलाने की कला पर 18 अध्याय हैं। इसमें ऐसे निर्देश भी दिये गये हैं कि किस प्रकार गैर इस्लामी शासन प्रणालियों के क्षेत्रों में स्थित व्यावसायिक भवनों एवं "आर्थिक केन्द्रों" पर बमबारी की जानी चाहिए। इससे अमरीकी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को इस बात की चेतावनी मिल जानी चाहिए थी कि कुछ विध्वंसकारी गतिविधियां होने वाली हैं। इसी साल के जून मास में भारतीय सरकार, इंटेलिजेन्स ब्यूरो तथा अमेरिका ने इन विस्तृत सूचनाओं पर चर्चा की थी कि बिन लादेन से जुड़े एक इस्लामी संगठन के ये संभावित प्रयत्न हैं कि दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास को उड़ा दिया जाये। ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास को भी उड़ा देने की योजना थी। इस सूचना पर भयंकर सन्देह व्यक्त किये गये। 1999 में अमेरिका की जानकारी में यह बात लाई गई थी कि जम्मू-कश्मीर में मारे गये भाड़े के एक आतंकवादी के पास से, अमेरिका द्वारा दिया गया, पायलट का लाइसेंस मिला है। यह जानकारी भी मिली कि उसने हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण जार्जिया और अटलाण्टा में प्राप्त किया गया। अनेक उपयोगी जानकारियों में यह जानकारी भी शामिल थी कि उग्रवादी इस्लामी संगठन अब बहुत सारे इंजीनियर एवं वैज्ञानिक भर्ती कर रहे हैं।

आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में सभी सभ्य देशों को भाग लेना चाहिए। अब समय आ गया है जब हर सरकार को अवांछनीय आतंकवादी गतिविधियों को सख्ती से कुचलना होगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। यूनाइटेड किंगडम जैसे देश तो उच्चकोटि की उदारता दिखाते हुए उग्रवादी इस्लामी संगठनों को इस बात की इजाजत देते रहे हैं कि वे संगठन वहां धन संग्रह करें, आतंकवादियों की भर्ती करें तथा जम्मू-कश्मीर, चेचन्या एवं अन्य पारस्परिक विरोध वाले क्षेत्रों में जाकर जिहादी आतंक फैलाने के लिये समुचित प्रशिक्षण प्राप्त करें।

बिन लादेन के संगठन अल-कायदा का एक अड्डा यूनाइटेड किंगडम में भी है जहां से वह आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करता है। 'दि टाइम्स' लंदन के डैनिएल मैकगारी एवं डोमिनिक केनेडी की रिपोर्ट पर आधारित दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक 'स्टेट्समैन के 27 सितम्बर, 2001 में प्रकाशित समाचार के अनुसार 11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका पर आक्रमण करने वाले विमान अपचालकों में से 11 लोग इस वर्ष के प्रारम्भ में ब्रिटेन में रहते थे। जांच करने वालों का विश्वास है कि वे आतंकी ब्रिटेन में धन-संकलन भी करते थे। अब फेडरेल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (एफ.बी.आई.) ने वहां ओसामा बिन लादेन के उन अड्डों की तलाश शुरू कर दी है जहां से आतंकवादियों ने, ऐसा विश्वास किया जाता है, 11 सितम्बर के आक्रमण में भाग लिया था।

इसी प्रकार यूरोप के बहुत से ऐसे देश हैं जो आतंकवादी गतिविधियों को रोकना तथा अपनी (उन देशों की) धरती से चलाए जा रहे आतंकवाद के जाल को बंद करना नहीं चाहते। इस दिशा में जर्मनी, स्विट्जरलैण्ड एवं स्कैंडिनेविया द. देशों के नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। (वि.सं.के.)

(प्रस्तुत लेख श्री एम.के. नारायणन के अंग्रेजी लेख पर आधारित है)।

पूर्वोत्तर का आतंकवाद भी पाकिस्तान से जुड़ा है

संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंकवाद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी है। उसकी घोषणा तो आतंकवाद को समूल नष्ट करने की है पर हो सकता है कि अरब ओसामा बिन लादेन और उसके समर्थकों को निशाना बनाने के बाद यह समाप्त हो जाये? हो सकता है कि इ सका उद्देश्य अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित प्रशिक्षण शिविरों और उनके छिपने के ठिकानों को नष्ट करने का भी हो अमेरिका के युद्धपोत जिस प्रकार से अरब सागर और हिन्द महासागर में एकत्र हुए हैं और अमेरिका ने दुनिया भर के देशों को आतंकवाद के खिलाफ जंग में शामिल करने के लिए एकजुट किया है, उससे लगता है कि उसका इरादा कुछ बड़ा कर गुजरने का है क्योंकि आंतकियों ने अमेरिका की शान विश्व वाणिज्य केन्द्र और शक्ति के प्रतीक पेंटागन को निशाना बनाकर विश्व की एकमात्र महाशक्ति को खुली चुनौती दी है। अमेरिका इसको पचा नहीं पा रहा है।

अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ सुविचारित अभियान का असर, दशकों से जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की मदद से आरम्भ आतंकवाद पर भी पड़ेगा। कारण अमेरिका की उपस्थिति में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान वहां पर आंतकियों को भेज नहीं सकेंगे। उनको हथियारों और अन्य प्रकार की मदद देने की स्थिति में भी नहीं होंगे। इसके साथ ही अन्य आतंकवादी संगठनों की शक्ति और प्रहार करने की क्षमता में फिलहाल कमी आ सकती है।

उधर उत्तर-पूर्व में आतंकवादी गिरोहों की संख्या काफी बढ़ी है किंतु उनमें से यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैण्ड आइजक-मुइवा (एनएससीएन-आईएम) इसका दूसरा खापलांग गुट, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी), यूएनएलएफ, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, (पीएलए), नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) सहित बीस बड़े आतंकवादी गिरोह हैं। एनएससीएन (खापलांग) को छोड़कर शेष सभी आतंकी गिरोहों के शिविर बांग्लादेश में है। इनका जाल देश के भीतर और बाहर फैला हुआ है। इनके कैम्प बांग्लादेश में होने के कारण इनको पाकिस्तानी आतंकवादी गिरोहों से हथियार, प्रशिक्षण, आर्थिक और सामरिक सहायता बराबर मिलती रहती है। एनएससीएन (आईएम) के महासचिव टी.मुइवा को 16 जनवरी 2000 को थाईलैण्ड पुलिस ने बैंकाक में उस समय गिरफ्तार कर लिया था जब वह पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस से उतर रहा था। वह कराची से वहां पहुंचा था। थाईलैंड पुलिस ने उसे जाली पासपोर्ट पर यात्रा करने के समय में गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद से नागा आतंकी गिरोह के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इण्टर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आई.एस.आई.) से संबंध होने का खुलासा हो गया था। मुइवा के कराची भ्रमण से कई प्रश्न उठ खड़े हुए। कारण पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर कराची में हरकत उल-मुजाहिदीन का मुख्यालय है। मुइवा के पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी गहरे संबंध है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसके साथ एनएससीएन के लिए हथियार की खरीद का प्रमुख अर्थाग शिमरे भी गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर-पूर्व के आतंकियों के हथियारों की आपूर्ति में आईएसआई की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उल्फा के बांग्लादेश में गिरफ्तार और वर्तमान में तीन साल की सजा भुगत रहे अनूप चेतिया ने भी बांग्लादेशी पुलिस से पूछताछ के दौरान बताया था कि वह थोड़े-थोड़े समय बाद पाकिस्तान जाया करता था। इससे साफ है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र के सभी आतंकवादियों का सरपरस्त पाकिस्तान ही है। स्वतंत्रता दिवस के कुछ दिन पहले 1999 में आईएसआई के चार एजेंट जमील बाकर, मौलाना हफीज, सलीम अहमद, और सैयद फसीउल्लाह गुवाहटी में पकड़े गये थे। यह घटना लोगों के दिमाग में अभी ताजा है। फसीउल्लाह और जमील पाकिस्तान के खुफिया अधिकारी है। जबकि मौलाना हफीज और सलीम अहमद हरकत उल-मुजाहिदीन के बड़े पदाधिकारी है। गुवाहटी पहुंचने के बाद वे असम के हरकत-उल-मुजाहिदीन के मुख्य संगठनकर्ता से बराबर सम्पर्क में थे। उनका उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस पर एक ही समय अनेक स्थानों पर बम विस्फोट कर तोड़फोड़ करना और साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाना था। सुरक्षा एजेंसियों ने ग्वालपाड़ा जिला के मौलाना फकरुद्दीन की पहचान हरकत-उल-मुजाहिदीन के नम्बर दो कमांडर के रूप में की। आईएसआई के लोगों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर राज्यभर में 27 इस्लामी आतंकवादियों की गिरफ्तारियां की गईं। इनमें से 16 आतंकियों ने हथियार चलाने और तोड़फोड़ करने का प्रशिक्षण पाकिस्तान के आतंकी प्रशिक्षण केन्द्रों में ली थी। इसके बाद असम में इस्लामी आतंकवादियों की गतिविधियों का भंडाफोड़ हुआ

था। ये चारों आतंकी पाकिस्तान से बांग्लादेश और वहां से बराकघाटी के रास्ते भारत में घुसे थे। भारत में इनको रुकने और यात्रा का प्रबंध करने में मस्जिद व मदरसे के लोगों ने मदद की थी। पुलिस ने इन लोगों से भी पूछताछ की थी किन्तु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया।

अब यह साफ हो गया है कि उल्फा के 200, हरकत-उल-मुजाहिदीन के 32, लस्करे तोयबा के 35 और हरकत-उल-इस्लाम के 30 आतंकियों का प्रशिक्षण पाकिस्तान में हुआ है। अलबदर के कुछ सदस्यों का प्रशिक्षण भी पाकिस्तान में हुआ है। यद्यपि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आतंकियों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआई के बीच संबंधों का पता हाल के वर्षों में हुआ किन्तु इनके सम्बन्ध इतने पुराने हैं कि ये आतंकी और नगा नेशनल कौंसिल (एनएनसी) के नेता ए. जेड फिजो तक जाता है। उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। उस समय फिजो ने अपने दूत भावू मोशी बिली को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त करने के लिए कराची भेजा था। मिजोरम के मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लालडेंगा को पाकिस्तान का समर्थन और संरक्षण प्राप्त था। गत एक दशक से उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आतंकवादियों और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के बीच मधुर संबंध विकसित हुए हैं।

खुफिया एजेंसियों के पास यद्यपि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आतंकवादियों के सम्बन्ध ओसामा बिन लादेन या उसके संगठन अल कायदा के साथ होने का प्रमाण नहीं है। तथापि 1996 में लादेन और कश्मीरी आतंकियों के संबंध होने की जानकारी स्पष्ट है। यह सच है कि हरकत-उल-मुजाहिदीन और लस्करे तोयबा ओसामा बिन लादेन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। फिर भी जब अमेरिका आतंकवादियों के खिलाफ पूरे दम से अभियान चलाएगा। तब पाकिस्तानी आतंकी गिरोह इनकी मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसी अवस्था में इनके हथियारों की आपूर्ति पर भी असर पड़ेगा। अमेरिकी हमलों में अफगानिस्तान के साथ ही पाकिस्तान के आतंकियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी हमलों का निशाना उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आतंकवादी नहीं बनेंगे किन्तु भारतीय सुरक्षा बलों और गुप्तचर एजेंसियों की नजरों से बचना उनके लिए आसान नहीं होगा। (वि.सं.के.)

आह्वान

- क्या आप देश की वर्तमान दशा पर चिन्तित हैं?
- क्या जड़ से शिखर तक व्याप्त भ्रष्टाचार आपको उद्वेलित करता है?
- क्या सामाजिक विषमता का विद्रूप आपको विक्षुब्ध करता है?
- क्या आपको लगता है कि यह सड़ी-गली, बीमार व्यवस्था बदल दिये जाने का समय आ गया है?
- क्या आपका दृढ़ विश्वास है कि यह परिवर्तन लाने में छात्र-युवा ही सक्षम हैं?
- क्या आप इसकी पहल अपने आप से करने को तैयार हैं?

यदि हाँ,
तो राष्ट्रीय छात्रशक्ति आपका आहवान करती है। आवश्यकता है जनजागरण के निरंतर अभियान की, देश के छात्र-युवाओं को अपने साथ जोड़ने की, संवाद स्थापित करने की। परिवर्तन के इस सर्जनात्मक अभियान में आपका योगदान अपेक्षित है।

अपने क्षोभ को शब्द दीजिये और विश्वास कीजिए,

आपमें क्षमता है कलम की नोंक से दुनियाँ का रूख बदलने की

अपने विचारों को साहित्य की किसी भी विधा में शब्द दें तथा

संपादक, राष्ट्रीय छात्रशक्ति, द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, 16/3676, रैगरपुरा, करोलबाग नई दिल्ली-110005 को प्रेषित करें।

तालिबानी आतंकवादियों की जन्मस्थली

तालिबानी आतंकियों की जन्मस्थली दशकों से आतंकियों के जन्मस्थल रहे पाकिस्तानी के सबसे बड़े इस्लामी मदरसे में लगभग 12 वर्ष के आयु के विद्यार्थी अपनी धार्मिक पुस्तक कुरान की पढ़ाई प्रारम्भ करने से पहले दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इस्लाम तथा मुसलमानों के शत्रुओं को शिकस्त दे तथा तालिबान को अमेरिकनों पर विजय प्रदान करे। इस्लाम की रक्षा की आग मन में संजोये हक्कानिया नामक मदरसे और सारे पाकिस्तान में फैले अन्य हजारों मदरसों के युवक विद्यार्थी अमेरिका के विरुद्ध जिहाद के लिए सहज ही उपलब्ध हैं। उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रान्त में स्थित एक मदरसे के विद्यार्थी 24 वर्षीय सैयद समीउल्लाह का कहना है कि आजकल हमारी बातचीत का विषय ही होता है कि क्या अमेरिका अफगानिस्तान पर आक्रमण करेगा? उनका कहना है कि वे तथा अन्य सभी विद्यार्थी जिहाद के लिये तैयार हैं।

11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका पर आतंकी आक्रमण ने पाकिस्तान को भी हिलाकर रख दिया है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान के विरुद्ध अमेरिका द्वारा फौजी कार्रवाई की स्थिति में पाकिस्तान द्वारा अमेरिका को सहयोग देने के निर्णय ले पाकिस्तानी सरकार तथा वहां के आतंकी मुस्लिम संगठनों (जिनमें कई हथियारों से सुसज्जित हैं) को आपसी टकराव की स्थिति में ला खड़ा किया है।

कुछ पाकिस्तानियों को भय है कि यदि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो आतंकी संगठन भी कार्रवाई शुरू कर देंगे।

1991 में रिटायर हुए जनरल मिर्जा असलम बेग का कहना है कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के क्रुद्ध युवकों से है जिनमें से अधिकतर निर्धन एवं बेरोजगार हैं और जिहाद के लिए भर्ती हो सकते हैं। हक्कानिया जैसे मदरसों के उन आतंकवादी संगठनों से गहरे सम्बन्ध है, जो गुरिल्ला प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों को भर्ती करते हैं। इनमें से अधिकतर भारतीय फौजों से लड़ने के लिए कश्मीर के उस क्षेत्र में भेज दिये जाते हैं जिसका भारत में विधिवत् विलय हो चुका है। पाकिस्तान के सभी धार्मिक मदरसों में से हक्कानियां सबसे अधिक आतंकवादी माना जाता है। तालिबान के बहुत सारे नेताओं ने यहां से शिक्षा प्राप्त की है। यहां शिक्षा प्राप्त करने वाले लगभग 3500 शिक्षार्थी सामान्यतः कुरान का अध्ययन करते है। जबकि पाठ्यक्रम में कुछ पंथनिरपेक्ष विषय जैसे गणित एवं भूगोल भी सम्मिलित हैं। यहां विद्यार्थी दरी पर पलथी लगाकर बैठते हैं तथा उनके सामने चौकियों पर कुरान रखी होती है। वे आगे पीछे झूलते हुए कुरान की आयतें दुहराते हैं। क्योंकि अधिकतर मदरसे पंजीकृत नहीं है अतः कुल मदरसों की संख्या ज्ञात नही है। गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार 30,000 से भी ज्यादा मदरसों में पढ़ने वाले शिक्षार्थियों की संख्या लाखों में है। अधिकतर मदरसे धनवान पाकिस्तानियों तथा अन्य मुस्लिम देशों से प्राप्त धन से चलते हैं। धार्मिक मदरसों की पाकिस्तान की गरीब जनता पर बड़ी मजबूत पकड़ है। ये गरीब घरों से आये शिक्षार्थियों को कट्टरपंथी शिक्षा ही नहीं वरन् भोजन वस्त्र, तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं भी प्रदान करते हैं। हक्कानियां का जिहाद का संदेश अन्य मदरसों की तुलना में अधिक जोरदार हो सकता है परन्तु विश्लेषकों की दृष्टि में अन्य मदरसे भी असहनशीलता फैलाने में कुछ कम नहीं है। मदरसों को पंथनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी करने के सरकार के सभी प्रयासों का अधिकतर मदरसों ने विरोध किया है। मदरसे युवकों को बताते हैं कि अमेरिका इस्लाम के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा है।

'अफगानिस्तान पर हमला करने से पहले अमेरिका को हजार बार सोचना चाहिए, 'यह कहना है हक्कानियां के अधिष्ठाता मौलाना सामीउलहक का। धार्मिक उन्माद का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी आक्रमण होने पर जिहाद एक आवश्यक कर्तव्य हो जायेगा और कोई नहीं कह सकता कि कब क्या हो जायेगा। इसी संदेश के सहारे तालिबान अमेरिका के विरुद्ध सारी दुनियां के मुसलमानों को संगठित करने का प्रयास कर रहे है। मदरसों में भी, जो नई पीढ़ी को शिक्षित करने में लगे हैं, यही संदेश गूंज रहा है।

Flood in Orissa and ABVP's role in Relief
A Report

If 1999 for Orissa was the year of calamity due to two successive cyclones the second one being popularly refered to as Super cyclone, the succeeding year 2000 was the year of super drought with continuous dry spell. The year 2001 too proved to be no better for Orissa with consistant rains for weeks together bringing flood in almost all the rivers of the state.

The state Revenu Minister Biswa Bhusan Harichandan who heads the Govt. mission to tackle the situation arising out of floods has him self gone on record saying that "this is the worst ever flood since independence" declaring the flood to be "super flood".

Mr. Harichandan is more then justified in saying so. As the meteorological office said from june 1 to July 18 the state so far has received 806.5 mm of rainfall in comparison to rainfall of 422 mm in normal times. At a time the water level in Hirakud dam touched 628.4 feet against its total capacity of 630 feet. A panic stricken state Government opened 51 out of 62 gates of the dam. Water release from Naraj reservoir touched 14 lakh cusecs one of the highest in last decade.

The impact was obvious on the rivers. 51 breaches took place among which 6 were in capital embankments that caused wide spread damages. Death toll in the ongoing flood touched 42 as per Government calculation. Government evacuated 1 lakh people from danger zones to safer place. But in the pick of the flood 10 lakh people were still marooned and trapped sans any communications with rest of the state. Though the state Government is yet to come out with exact loss property, cropes, houses, live stock and so on the Chief Secretary has officially said that the loss would run into thousand crores.

Immidiately with the flood ABVP Units pressed themeselves to action While Puri Vivag Organising Secretary Prakash Mangaraj led the work in Kanasa Block in worst affected Puri district, Gopinath Sahoo State Secretary was in Aul of Kendrpara and mobilised ABVP workers for relief work. Nirmal Sarangi Dhenkanal Vivag organising Secretary was in Athmallick one of the worst affected place in Angul district.

In a span of two three days our workers collected relief material and cash. 100 ABVP workers were engaged in the relief work and the work was going on in 6 worst affected districts such as Puri, Kendrapara, Jagatsinghpur, Jaipur, Bhadrak and Angul, ABVP workers too participated in the relief operations as carried by RSS sponsored voluntary organisation Utkal Bipanna Sahayata Samiti (UBSS).

As the rainfall stopped, water level in dams and reservoirs gone down and revers gradually going below danger level - now the major challenge would be relief and rehabillitation. ABVP is determined to be with people in trouble in what ever small way that might be.

From Page No. 4....

Obituary of Gowri Shankarjee

from Hyderabd.

The A.P unit has written many historical chapters in the Nationalist students movements demonstration infront of Secretariat as a part of Lok-abhiyan, the first Anti-Naxal violence demonstration (14.12.1983), Eye camps in rural areas (1982-85), district conference (1985), agitation against capitation fee (1983-86), Anti-Naxal movement, agitation against beauty contests was on obscenity, various experiments on organizational training, code of conduct for student unions, Prerana-Literary groups, save democracy movement, pro-reservation movement, Ayodhya movement, Kashmir movement were the only samples. Historical demonstrations in 1991, 1996, 2000 were held during his tenure.

Not only to State level work, Gowrijee has contributed much to National works also. Visualising big conferences (Delhi, Kanpur, Mumbai), giving proper guidance with regard to workers training and shaping orgaisational traditions were contributions of Gowrijee.

We pray almighty "May his soul rest in eternal peace".

TIDE WILL TURN IN OUR FAVOUR

Students for Development, a forum sponsored by Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad in the field of Development, organised a highly interactive seminar on "Synergy Between Industry and Technical Institutions: Opportunities and Challenges".

Prof. V.S. Raju from IIT Madras, who is also former director of IIT, Delhi and Mr. Subhash Jagota, Executive Director. HRD Punj Lloyd Ltd. shared their experience with the students and responded to their queries.

Dr. Ashok K. Chauhan, founder president of the Ritnand Balved Education Foundation, which is the umbrella body of more than 30 Amity schools and institutions of higher education, was the chief guest. He told the students with excerpts from his vast repertoire of experience.

"The present slowdown in the IT industry is making people nervous expecially in the U.S. and India. But it is a matter, of three to nine months when the revival will occur. In between you must equip yourself with unique knowledge. History is witness that the biggest success stories have been written during the time of recession. Make SFD a platform for launching of success stories," he said.

Prof. Raju said, "About 20 years back, industry and academics were considered independent of each other. But now there is no dispute over the need for synergy between the two Close Links create a win-win situation in which both partners benefit.

"Since 90 percent of all graduates go to the industry, it is important that institutes give industry-oriented knowledge. This serves a mutually beneficial purpose," he said.

"In a knowledge driven economy where the globe is the market, the key factor is the quality of people. The industry wants bright, young talent. There exists an undeniable synergy between the two and one plus one can become 11 if adequately correlated." he said

While consenting that the sentiments in the economy are at an all time low, he said that there is a slowdown but the globle economy will pick up again. The future will be brighter for those who continue to feel confident. Replying to queries from the students about the future of non-IIT alumni he said. "Given the vast reservoir of bright talent in our contry. We need a large number of institutions. Having a handful centres of excellence is not enough. Even the Prime Minister understands this need and the government is working on a plan to encourage private institution. Those not in IITs merely have to work a little more than IIT-ians".

"Moreover, being an IIT-ian helps only in the initial stages. Five years into the industry no one will see which institution you belong to. They will only see what work you have done," he said.

The seminar was attended by more than 160 students from various information technology and engineering institutions. A Q&A session was also organised to clear doubts and apprehension of students. The participants had came to the conclusion that interaction between industry and students needs to be enhanced. The suggestion was made to initiate an open dialogue with the sectors related with technology in any manner. This way students can develop the skills and will get equipped to face the challenges they have to subsequently face in the industry.

• Neeraj Gupta, Abhishek Bhasin, Jugnu Bhatia, Dheeraj Mutreja, Ms. Deepali Agarwal, Megha Singh, Vimmi Gupta and Kavita Gupta were the members of organising committee.

जाति एवं नस्ल में अन्तर है

नस्लवाद, नस्ल के आधार पर भेदभाव, विदेशी-द्वेष या भीति एवं तत्सम्बन्धित असहिष्णुता के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा डरबन में आयोजित विश्व सम्मेलन एक महत्वपूर्ण घटना है। जन साधारण के लिए "नस्लवाद" एवं "विदेशी भेद व भीति" जैसे शब्दों का सही अर्थ समझ पाना आसान नहीं है। तो भी, यह विचित्र है, कि भारत में इस सम्मेलन के विषय पर गरमा-गरम बहस हो रही है। अंग्रेजी समाचार पत्र-पत्रिकायें तो इस बहस से सराबोर हैं किन्तु अधिकांश हिन्दी दैनिकों ने अपने को इससे दूर रखा है। इस महत्वहीन मुद्दे पर अंग्रेजी दैनिक लेखों पर लेख क्यों उड़ेल रहे हैं? क्या भारत में, ऐसे लेख लिखने के लिये प्रेरणा एवं समर्थन देने वाली कोई संस्था है जो पर्दे के पीछे रहते हुए काम कर रही है? इस सारे शोर-शराबे के पीछे क्या कोई विदेशी मिशनरी समर्पित गैर शासकीय संस्था है? इसकी जांच-पड़ताल तहलका टीम अपने विचित्र तरीकों से कर सकती है। प्रमुख रूप में अधोलिखित बिन्दु उल्लेखनीय है।

1. भारत सरकार को डरबन-सम्मेलन के एजेण्डा में जाति या जातिवाद के मसले को शामिल करना चाहिए।
2. एजेण्डा में जातिवाद को शामिल न करके भारत सरकार ने दलितों के साथ अपकार किया।
3. नस्ल एवं जाति, दोनों एक ही हैं और नस्ल-आधारित भेदभाव एवं जाति-आधारित भेदभाव में कोई अंतर नहीं है।
4. भारत एक बहुनस्लीय देश है और अनेक नस्लों का अप्रतिष्ठीकरण कर के नीची जातियां बना दी गई हैं।
5. दलित इस नस्ल या जाति के विभेदीकरण से सर्वाधिक यातना भोग रहे हैं।
6. विश्व सम्मेलन को ऐसे मार्ग एवं साधन जताने चाहिए जिनसे भारत में जातिवाद का अन्त हो सके।

दलितों के वांछित भाष्यकार, लेखक एवं तथाकथित विद्वान जन एक बड़े साधारण तथ्य को नजरअंदाज कर जाते हैं कि जाति नस्ल नहीं है और नस्ल जाति नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर ने 9 मई, 1996 को अमेरिका में न्यूयार्क नगर के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में अपना पहली शोध प्रबंध (थीसिस) जमा किया था। थीसिस का विषय था, "कास्ट्स इन इंडिया-जेनिसिस एंड डिवेलपमेन्ट" (भारत में जातियां-उत्पत्ति एवं विकास)। यह शोध-प्रबंध "डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर-राइटिंग्स एंड स्पीचेज" के चतुर्थ खण्ड में प्रकाशित हुआ है। इसी शोध-प्रबंध से उद्धृत सामग्री यहां प्रस्तुत है। भारतीय समाज की संरचना का उल्लेख करते हुए ("पृष्ठ 6 पर") डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं :-

"नृजातीय दृष्टि से सभी लोग वैषम्यपूर्ण होते हैं। ("एथनिकली आल पीपुल आर हेटरोजेनस") अंग्रेजी भाषा में किन्तु, "एथनिक" शब्द का अर्थ वास्तव में विशुद्ध नृजातीय या मानव जातीय नहीं है। चैम्बर्स इंग्लिश डिक्शनरी में इस शब्द का अर्थ है—राष्ट्रों या नस्लों से सम्बन्धित, गैर यहूदी, गैर ईसाई, गैर मुसलमान, मूर्तिपूजक, विधर्मी म्लेच्छों के साथ अनुकूलताप रखने वाली)। सांस्कृतिक एकता ही वह तत्त्व है जो उनमें समरसता का आधार बनती है। इस बात को ध्रुव सत्य मानकर मैं यह कहने की जोखिम उठा रहा हूं कि भारतीय प्रायदीप की सांस्कृतिक एकता का मुकाबला करने वाला कोई देश नहीं है। इसकी न केवल भौगोलिक एकता है, सबसे बढ़-चढ़कर, बहुत गहरी और कहीं अधिक मूलभूत एक (और) एकता है-देश के एक छोर से दूसरे छोर तक छाई असंदिग्ध एवं सुनिश्चित सांस्कृतिक एकता। किन्तु इसी समरसता के कारण जाति एक ऐसी जटिल समस्या बन जाती है जिसकी व्याख्या करना कठिन होता है। यदि हिन्दू समाज पारस्परिक विशिष्टता पूर्ण इकाइयों का केवल एक संघ होता तो बात काफी आसान थी। किन्तु जाति एक पहले से ही समरसता पूर्ण इकाई का संविभाजक तत्व है, और जाति की उत्पत्ति की व्याख्या करने का अर्थ है संविभाजन की इस प्रक्रिया की व्याख्या।"

तदुपरान्त डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर इस बात की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं कि बहुत पहले यह संविभाजन-प्रक्रिया किस प्रकार हो सकी होगी। उनका सम्पूर्ण विश्लेषण अत्यन्त मर्मस्पर्शी एवं विलक्षण है। अन्तर्जातीय विवाहों का अप्रचलन सारी व्याख्या का सार है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, "समाज सदैव वर्गों से निर्मित होता है। और यह एक विश्व व्यापक तथ्य है, और प्रारंभिक हिन्दू समाज इस नियम का अपवाद नहीं हो सकता था।" डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि पहले चार वर्ग

थे—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ये वर्ग एक वर्ग में कैसे परिणत हो गए? डॉ. अम्बेडकर कहते हैं (पृष्ठ 15) जाति की उत्पत्ति का अध्ययन हमें निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर देगा—यह कौन-सा वर्ग है जिसने अपने चारों ओर इस अनुलग्नक को खड़ा किया? मैं इसका उत्तर केवल परोक्ष रूप से दे सकता हूं। मैंने अभी ऊपर कहा है कि विषयगत प्रथायें हिन्दू समाज में प्रचलित थीं। तथ्यों के साथ ईमानदारी बरतने के लिए यह आवश्यक है कि इस कथन के वैशिष्ट्य को समझा जाये, क्योंकि यह उनके प्रचलन की सार्वभौमिकता की ओर संकेत करता है। कड़ाई से पालन की जाने वाली ये प्रथायें केवल एक जाति में मिलती हैं, जिसका नाम ब्राह्मण है, जो हिन्दू समाज के सामाजिक पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान पर आसीन है। यह महत्वपूर्ण तथ्य एक महत्वपूर्ण अध्ययन का आधार बन सकता है तब तो सिद्ध करने के लिये किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। जाति-संस्था का जनक कौन-सा वर्ग है? हमारे अनेक तथाकथित सेक्युलरिस्ट एवं प्रगतिशील नागरिक एक वह तर्क सामने रखते है कि भारत में जाति प्रथा के जनक मनु हैं। जब वे कहते हैं कि ब्राह्मण जाति प्रथा के रचयिता हैं तो उनके हृदय आनन्द से भर जाते हैं। अभी भी ऐसे बहुतेरे हैं जो डॉ. बाबा साहेब के अनुयायी होने की बात जोर-जोर से चिल्लाते हैं, और सेक्युलरिस्ट प्रगतिशीलों की ताल में ताल मिलाते हैं। उनको यह परामर्श दिया जाना चाहिए कि एक क्षण भर के लिए रुकें और बाबा साहेब अम्बेडकर की कलम से लिखी एवं अधोउद्धृत सामग्री को पढ़े :-

"एक बात मैं आपके मन में बैठा देना चाहता हूं वह यह है कि जाति के नियम मनु ने नहीं दिये हैं, और वे ऐसा नहीं कर सकते थे। जाति व्यवस्था मनु से बहुत पहले थी। उन्होंने उसका केवल अनुमोदन किया, और उसके विषय में दार्शनिक भाव प्रदान किया, परन्तु हिन्दू समाज की वर्तमान व्यवस्था को विहित करने का काम उन्होंने नहीं किया, कर भी नहीं सकते थे। वर्तमान जाति-व्यवस्था से सम्बन्धित नियमों को संहितावद्ध करने एवं जातिधर्म के विषय में उपदेश देने के पश्चात् उनका कार्य समाप्त हो गया था। जाति व्यवस्था का प्रसार एवं विकास एक अति विशाल कृति है जो किसी एक व्यक्ति या वर्ग की चालाकी या पूर्ण शक्ति से सम्पन्न नहीं हो सकता था। ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था की रचना की—यह सिद्धान्त भी, तर्क में, वैसा ही है। मनु के विषय में इतना कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हां यह अवश्य उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का विचार सही नहीं है, विद्वेष मूलक एवं अहितकर है। ब्राह्मण अनेक बातों के लिये दोषी हो सकते हैं, और मेरी मान्यता है कि वे थे, किन्तु गैर ब्राह्मण आबादी पर जाति व्यवस्था थोपना उनके बलबूते के बाहर था।" (पृ.16)

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अपने शोध प्रबंध का समापन इस प्रकार करते हैं (पृ. 29) :-

"मेरी राय में जाति विषय के विद्यार्थियों ने अनेक गलतियां की हैं जिनसे वे अपने अनुसंधानों में दिग्भ्रमित हुए हैं। जाति व्यवस्था का अध्ययन करने वाले योरोप के विद्यार्थियों ने जाति प्रथा में रंग की भूमिका को अनावश्यक तूल दिया है। स्वयं रंग सम्बन्धी पूर्वाग्रहों एवं प्रतिकूल प्रभावों से सराबोर उन्होंने फटाफट यह कल्पना कर ली है कि जाति समस्या में रंग ही प्रमुख निमित्त है। किन्तु यह बात सच्चाई से सर्वाधिक दूरी पर है। डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि "सारे राजा चाहे वे तथाकथित आर्य-नस्ल के हों या तथाकथित द्रविड़, इस प्रश्न ने भारत के लोगों को कभी व्यथित नहीं किया। यह तभी शुरू हुआ जब विदेशी छात्र भारत में आए और उन्होंने दोनों के बीच एक लकीर खींच दी। त्वचा के रंग का महत्व बहुत पहले समाप्त हो गया था।" मेरे जाति समस्या पर अध्ययन में प्रमुख रूप से चार मुद्दे जुड़े हैं :-

1. हिन्दू समाज की बहुघटकीय संरचना के बावजूद इसमें एक गहन सांस्कृतिक एकता है।
2. जाति व्यवस्था, एक वृहद्तर सांस्कृतिक इकाई को, टुकड़ों में विभाजित करती है।
3. प्रारम्भ में केवल एक ही जाति थी।
4. अनुकरण या बहिष्कार के माध्यम से वर्ग जातियों में बदल गये।

जाति नस्ल नहीं है, नस्ल को जाति के समतुल्य मानने में इसाई लॉबी के दूरगामी व्यापक एवं निहित स्वार्थ है। मुक्ति या परिमोचन का धर्मशास्त्र उनकी जेबों में है। यदि दलितों को एक अलग नस्ल मानने की घोषणा हो जाए तो वे अपने आप ही अहिन्दू हो जायेंगे। वे गत दस या बारह वर्षों से जोर-जोर से, गला फाड़-फाड़कर यह प्रचार कर रहे हैं कि दलितों को भारत के देशी लोग होने की घोषणा कर दी जाए। मिशनरी लॉबी की इस घृणित एवं चालाकी पूर्ण षड्यंत्र से बचना चाहिए। (विसंके)

(लेखक मराठी साप्ताहिक 'विवेक' के सम्पादक हैं।)